THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) The Textile Research Associations have on the instructions of the Ministry of Textiles, prepared schemes for the modernisation of 79 mills of NTC at an expenditure of Rs. 2005.67 crores. The modernisation paln also involves the restructuring of 36 unviable units into 18 viable units. It is expected that NTC would be able to attain viability within two years of implementation of this plan. This plan has been submitted to the Special Committee for consultation on NTC matters and would require the approval of the Board for Industrial and Financial Reconstruction under the provisions of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 before implementation.

(c) About 25,000 workers of NTC are being paid idle wages of about Rs. 8 crores per month.

(d) The accumulated net loss of NTC as on 30-9-1993 was provisionally Rs. 3240 crores. The amount of interest waived by the Government is Rs. 1162.89 crores. The amount of debt of NTC mills as on 30-9-1993 was Rs. 2873.49 crores.

(e) Government are willing to handover the mills of NTC to Workers' Cooperatives provided a concrete and viable proposals is received in this regard having the consent of all parties concerned.

**राष्ट्रीय वस्त्र निगम की इकाइयों में वित्तीय संकट**

2230. **श्री राम जेठमलानी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी 1994 के दैनिक ओबजरवर में प्रकाशित "एन टी सी सीक्स गवर्नमेंट हैल्प टू वेजिज" शीर्षक समाचार की ओर दलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के तहत कई इकाइयों में कर्मचारियों को वेतन देने हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी इकाइयों की संख्या कितनी है और उनमें कितने अधिक श्रमिक काम करते हैं और उनका मासिक वेतन बिल कितना है ;

(घ) क्या सरकार ने इन इकायों की यह दयनीय आर्थिक स्थिति होने से पूर्व इनमें सुधार के लिए कोई निर्देश जारी किए थे या कोई उपाय किए थे ;

(ड.) यदि हां, तो कब और क्या उपाय किए गए थे ; और

(च) इन इकाइयों के प्रति अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी)** : (क) जी हा ।

(ख) एन टी सी को हो रहे निरंतर घाटों के साथ-साथ बजटीय कठिनाईयों के कारण उनकी प्रतिपूर्ति की राशि में कमी आने से एन टी सी मे द्रव्यता की कमी हो गई है । इसके फलस्वरूप वह अत्याधिक कठिनाई से अपने कामगारों को वेतन का ही भुगतान कर पा रहा है ।

(ग) एन टी सी की 39 मिलों में आंशिक अथवा कोई भी क्रियाकलाप न होने के कारण लगभग 25,000, कामगारों को लगभग 8 करोड रु० प्रति माह की राशि का काम के बिना वेतन का भुगतान किया गया है ।

(घ) से (च) सरकार ने एन टी सी के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चुनिदां आधुनीकीकरण वित्तीय तथा प्रबंधकीय पुर्ननिर्माण, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना जारी द्वारा फालतू काम गारों का सुव्यस्थीकरण तथा अंतरिम द्रव्यता का प्रावधान करना शामिल है ।

इस सर्वांगीण सुधार नीति के सफल क्रियान्वयन से ऐसी आशा है कि तीन वर्षों में एन टी सी लाभप्रदता प्राप्त कर लेगा । औद्योगिकी तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 के उपबन्धों के अंतर्गत एन टी सी का पुरुधार करने के लिए आवश्यक उपायों का पता लगाने तथा उन्हें लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है ।

**राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण इकाइयों को बन्द किया जाना**

2231. **श्री एस. एस. अहलुवालिया :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की लगातार घा देने वाली मिलों को बन्द कर देने का फैसला कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार से इस फैसले से कितने कामगारों के बेकार हो जाने की संभावना है ; और

(घ) सरकार ने बेकार होने वाले कामगारों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए है ?

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) :** (क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय के निदेशों पर वस्त्र अनुसंधान संघ ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पुनरुद्धार के लिए 2005.67 करोड रु. के व्यय से एक नई आधुनिकीकरण योजना तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 36 गैर अर्थक्षय एककों का 18 अर्थक्षय एककों में पुनः संरचना करना शामिल है ।

(ग) वस्त्र अनुसंधान संघ द्वारा तैयार योजना में स्वच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत 70885 फालतू अधिकारियों कर्मचारियों और कामगारों का सुव्यवस्थीकरण करने की परिकल्पना की गई है और 28-2-94 तक 33245 अधिकारी कर्मचारी तथा कामगार इस योजना का पहले ही लाभ उठा चुके हैं ।

(घ) सरकार ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठाने वाले कामगारों के पुनःप्रशिक्षण तथा पुनर्निर्माण के लिए 50.00 करोड रु. की धनराशि से एक पुनर्वास निधि स्थापना की है । ऐसे सुव्यवस्थीतकृत कामगारों को विद्युत करघा रोलिंग एककों के छः माह तक सफलता पूर्ण चलाने के पश्चात् उद्यम को और अधिक लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत पूंजी लागत का 25% से 33% का उत्पादन प्रोत्साहन दिया जाता है ।

**Import of cotton**

2232. DR. NAUNIHAL SINGH:
SHRI RAM RATAN RAM:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that cotton prices have not eased in this domestic market even a week after the doban on cotton exports;

(b) if so what are the reasons therefor;

(c) what volume of cotton is intended to be imported, how much will it cost in terms of dollers and from which country/ countries it is intended to be imported;

(d) to what extent these decisions have helped the cotton growers; and

(e) what extent it has helped to curb the undue rise in cotton prices.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) Though the prices of cotton have not come down; the suspension